(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में स्थापित किए गए ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है और इसके साथ ही उन जगहों के नाम क्या हैं, जहां ये स्थापित किए गए हैं ; और

(ग) इन उद्योगों में लगी पूरी पूंजी कितनी है और कितने लोगों को इनमें रोजगार दिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्ष के दौरान पंजाब में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई नया उद्यम स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) 31-3-1989 तक पंजाब में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अक्त परिसम्पत्ति के रूप में कुल पूंजीनिवेश 802.76 करोड़ रु. का था तथा उक्त तारीख तक कर्मचारियों की कुल संख्या 0.23 लाख थी।

Winding up of MRTP Commission

1523. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the M.R.T.P. Commission has since been rendered paralysed by Government by not appointing new incumbents against vacant posts due to the retirement of two of its three members and premature death of one member;

(b) whether Government are contemplating to wind up the said Commission; and

(c) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI AJIT SINGH): (a) No, Sir. Action is under way to fill up the vacant posts.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

टिहरी बांध से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था

1524. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार अवतार सिंह अरोड़ा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टिहरी बांध के निर्माण के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण के कारण कितने परिवार बेघर तथा बेरोजगार हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सरकार ने उनके पुनर्वास और पुनः रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री, राज्य में कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) सरकार ने नवम्बर, 1986 में टिहरी पन विद्युत परियोजना कमलेक (2,400 मेगावाट, जिसमें टिहरी बांध परियोजना शामिल है, को भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में कार्यान्वित किए जाने और इसके लिए सांविधिक मंजूरी तथा वित्तीय सहायता प्राप्त किए जाने का निर्णय किया गया था। इस निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) टिहरी बांध के निर्माण के फलस्वरूप 3500 शहरी परिवार तथा 9860 ग्रामीण परिवार प्रभावित होंगे जिनमें से 5550 ग्रामीण परिवार केवल आंशिक रूप से प्रभावित होंगे। प्रथम चरण में, 1924 पूर्ण रूप से प्रभावित परिवारों में से 1880 का पहले ही पुनर्वास किया जा चुका है।

परियोजना प्राधिकारियों द्वारा तैयार किए गए एक विस्तृत मास्टर प्लान के अंतर्गत लगभग 268 करोड़ रु. पुनर्वास संबंधी उपायों पर खर्च किए जाएंगे। पुनर्वास योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित उपायों के माध्यम से क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है—सिंचाई भूमि के बदले भूमि का आबंटन किया जाना अथवा नकद क्षतिपूर्ति एवं अनुग्रह-राशि का भुगतान किया जाना, भूमिहीन कृषि मजदूरों को भूमि दिया जाना, मकान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाना एवं मकान के निर्माण के लिए वास्तविक लागत आधार पर आवासीय प्लाट आबंटित किया जाना तथा अन्य लाभ प्रदान किया जाना। नए टिहरी टाउन में शहरी पुनर्वास हेतु उपर्युक्त आकार के भूमि प्लाट रियायती दर पर आबंटित किए जाते हैं और वाणिज्यिक वस्तुओं तथा घरेलू सामान की ढुलाई के लिए नकद भुगतान किया जाता है।

रोजगार के मामले में, प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

Plan to increase power supply in Delhi

1525. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether any fresh plan has been worked out for increasing power supply in Delhi; and

(b) if so, what are the details thereof and by when the same is likely to be implemented?

THE MINISTER OF ENERGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) and (b) With a view to augment the power supply in Delhi the 2x67.5 MW Rajghat Thermal Replacement Unit have been commissioned recently. Installation of 3x30 MW Waste Heat Recovery Units at the existing Gas Turbines and setting up of a 800 MW Combined Cycle gas-based project at Bawana are also likely to be implemented during the Eighth Five Year Plan subject to availability of resources and other inputs.

Import of Danazol

1526. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether his Ministry have received representations in the recent past for banning the import of Danazol;

(b) whether it is also a fact that this drug is produced in the country in much excess quantity than its requirement and is being exported to USA, UK, USSR and other countries;

(c) whether it is also a fact that request for ban on import is pending for the last two years and no action has been taken thereon;

(d) whether it is also a fact that this drug is being offered in domestic market at a lower price than the landed cost of imports;

(e) if so, what are the reasons therefor; and

(f) by when the import of this drug is likely to be banned and valuable foreign exchange saved?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a), (c) and (f) Yes, Sir. However, the Policy for putting the item in various Appendices of EXIM Policy, is decided by Ministry of Commerce in consideration of various factors such as, demand, number of manufacturers, production, availability etc.

(b) The production of this drug is not monitored by this Department. Export of individual drugs is not being monitored by this Department.

(d) and (e) Danazol is not price controlled under the drugs (Price Control) Order, 1987. M/s. CIPLA vide, their letter dated the 24th Jan., 1990 reported that landed cost of import of this drug during 1987-88 was Rs. 49,670 per kg. against which they would be offering this drug in the country at Rs. 33,000 per kg.